



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 11 सितंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 342

महत्वपूर्ण एवं खास

भारत-अमेरिका ने ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने पर जताई सहमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत और अमेरिका ने आपसी सहयोग के क्षेत्रों की लिस्ट में उभरते ईंधन को शामिल कर ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस लिस्ट में बिजली और ऊर्जा दक्षता, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत वृद्धि को पहले ही शामिल किया गया है। तेल मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि इस घोषणा के बाद गुरुवार शाम को अमेरिका-भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई। बयान में कहा गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एससीईपी के तहत अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेफिफर ग्रानहोम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की। बयान में अधिक विवरण दिए बिना कहा गया, 'बैठक में भारत-अमेरिका असाइन परमाणु ऊर्जा सहयोग की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

ग्राहकों, यात्रियों के टीकाकरण का पता लगाने को-विन ने जारी किया नया एपीआई

नई दिल्ली (आरएनएस)। को-विन ने एक नया एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) 'नो थॉर कस्टमर/क्लाइंट वैक्सीनेशन स्टेटस (केवाईसी-वीएस) बनाया है, जिससे कोई निकाय पता लगा सकता है कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस रोधी टीका लगवा चुका है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। देश में इस साल 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अब तक 72 करोड़ से अधिक खुराक लगाई जा चुकी हैं। टीका लगवाने वाले लोग को-विन से डिजिटल तरीके से प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसी तरह मॉल, कार्यालय परिसरों, सार्वजनिक आयोजनों आदि में प्रवेश के लिए इस तरह के प्रमाणपत्रों को डिजिटल या प्रत्यक्ष स्वरूप में दिखाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां किसी संस्था या निकाय को सभी के प्रमाणपत्र देखने की जरूरत नहीं है और केवल यह पता लगाना होता है कि किसी व्यक्ति ने टीका लगवाया है या नहीं। उसने कहा कि कोई उद्यम या नियोक्ता अपने कार्यालयों, कार्यस्थलों में कामकाज बहाल करने के लिए अपने कर्मचारियों के टीकाकरण का स्तर पता लगा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि रेलव अपने उन यात्रियों के टीकाकरण के बारे में जानना चाह सकता है जो सीट आरक्षित करा रहे हैं। एयरलाइन भी ऐसा कर सकती हैं। होटल अपने यहां ठहरने वाले लोगों के बारे में पता कर सकते हैं कि उन्होंने टीका लगवाया है या नहीं।

देश में दो दिन उछाल के बाद तेजी से गिरा कोरोना ग्राफ

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना महामारी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले दो दिन में बड़े उछाल के बाद पिछले 24 घंटे में नौ हजार की कमी के साथ 34,973 नए मामले सामने आए। जबकि संक्रमण के कारण 260 मरीजों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,31,74,954 हो गई। आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 260 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,42,009 हो गई। देश में अभी 3,90,646 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.18 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 2,968 की कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.49 प्रतिशत है। मंत्रालय आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में जिन 260 लोगों की मौत संक्रमण से हुई, उनमें से केरल के 125 लोग और महाराष्ट्र के 55 लोग थे। महाराष्ट्र ने आंकड़ों का पुनःमिलान किया है, जिससे बुधस्वितवार की तुलना में कुल मामलों और संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से अभी तक संक्रमण से कुल 4,42,009 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,38,017 लोग, कर्नाटक के 37,462 लोग, तमिलनाडु के 35,094 लोग, दिल्ली के 25,083 लोग, उत्तर प्रदेश के 22,863 लोग, केरल के 22,126 लोग और पश्चिम बंगाल के 18,539 लोग थे।

भारत को मिलने वाला 36वां राफेल सबसे अधिक घातक

नई दिल्ली (आरएनएस)। फ्रांस अगले तीन महीनों तक भारत तो हर महीने तीन राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी देगा। इसके साथ ही दिसंबर 2022 तक 35 लड़ाकू विमान भारत को मिल जाएंगे। 36वें लड़ाकू विमान की डिलीवरी जनवरी में होगी। आपको बता दें कि 4.5 पीढ़ी के 26 राफेल लड़ाकू विमान पहले से ही अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं। तीन और डसॉल्ट निर्मित लड़ाकू विमान 13 अक्टूबर को अपने करीबी सहयोगी यूईई मिड-एयर रिफ्यूएलर की मदद से जामनगर बेस पर उतरेंगे। नवंबर में तीन और और अन्य तीन दिसंबर में भारतीय वायु सेना में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि, 36वां राफेल फाइटर अधिक घातक होगा। उसे भारत के द्वारा और अडवांस बनाया जाएगा। आपको बता दें कि राफेल को हैमर एयर टू ग्राउंड, एससीएएलपी जमीनी हमले में



सक्षम बनाया गया है। ये लड़ाकू विमान अधिक ऊंचाई और अधिक सटीकता के साथ अधिक रेंज वाले उल्कापिंड मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम हैं। 36वें लड़ाकू विमान इजरायली मूल की कुछ टेक्नोलॉजी के साथ उतारने की तैयारी है। राफेल लड़ाकू विमान अधिक शक्तिशाली रेडियो अल्टीमीटर, रडार ग्राउंड, एससीएएलपी जमीनी हमले में

चुका है। उल्का मिसाइल भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। हैमर और एससीएएलपी ने अंतिम-मिनट में टारगेट को भेदने में दक्ष है। यह रडार से बचने में भी माहिर है। इन हथियार प्रणालियों में कई मार्गदर्शन सुविधाएं होती हैं ताकि दुश्मन के पास मिसाइल को हवा से हवा या जमीन पर हमला करने का कोई मौका न हो और 70 किलोमीटर दूर से भी स्टैंड-ऑफ मोड में इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रान्त के लिए अगले अगस्त में लॉन्च होने वाले राफेल-समुद्री लड़ाकू विमान के विकल्प की भी जांच कर रही है। वहीं, वायु सेना को राफेल की बढ़ी हुई क्षमता के कारण अपने लड़ाकू स्काइड की ताकत को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा गया है।

सुशिवानी खुली खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शिवानी मीणा को कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की प्रथम उत्खनन इंजीनियर बनने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इससे महिला पेशेवरों के लिए खनन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति इरानी ने भी शिवानी की इस उपलब्धि के लिए उनकी सराहना की है। सुशिवानी मीणा रजरप्पा परियोजना में एक उत्खनन इंजीनियर के रूप में शामिल हुई हैं, जो कि सीसीएल के रजरप्पा क्षेत्र में एक मशीनीकृत खुली खदान है। यह अपने आप में अभूतपूर्व

है क्योंकि सुशिवानी उत्खनन संवर्ग की पहली महिला इंजीनियर हैं, जो एक खुली खदान में काम कर रही हैं। उन्हें हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का रखरखाव और मरम्मत करने की जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि रजरप्पा सीसीएल की महत्वपूर्ण परियोजना है। कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में रजरप्पा क्षेत्र को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। शिवानी राजस्थान के भरतपुर की मूल निवासी हैं और उन्होंने आईआईटी, जोधपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। सुशिवानी अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती हैं और बताती हैं कि यह उनके परिवार का अटूट समर्थन था जिसने उन्हें प्रेरित किया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक पदक विजेताओं और भारतीय दल के सदस्यों को सम्मानित किया

मंत्रालय ने पहली बार पैरालंपिक विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठवलने ने आज नई दिल्ली स्थित होटल अशोक के कन्वेंशन हॉल में आयोजित एक समारोह में टोक्यो 2020 पैरालंपिक पदक विजेताओं और भारतीय दल के अन्य सदस्यों

और उनके कोचों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह का आयोजन विकलांगता अधिकांश विभाग द्वारा किया गया था। भारतीय पैरालंपिक समिति के पदाधिकारी- अविनाश राय खन्ना, मुख्य संरक्षक, सुदीपा मलिक, अध्यक्ष और गुरशरण सिंह, महासचिव, सुअंजलि भवरा, सचिव, विकलांग अधिकारिता विभाग और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अभिनंदन समारोह में मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सभी पदक विजेताओं और भारतीय पैरालंपिक टीम के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्र को गौरव दिलाने में उनके उत्कृष्ट प्रयास के लिए बधाई दी। उन्होंने देश में विश्व स्तर के दिव्यांग खिलाड़ियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय पैरालंपिक टीम के कोचों की भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कामना की कि दिव्यांग खिलाड़ियों, उनके कोचों और उनके परिवारों के संयुक्त प्रयासों से पैरालंपिक खेलों में वृद्धि जारी

रहेगी और अगले पैरालंपिक में भारतीय पदकों की संख्या दोगुनी होगी। राज्यमंत्री रामदास अठवलने ने देश के लिए रिकार्ड संख्या में पदक जीतने के लिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए पूरे भारतीय पैरालंपिक दल, उनके एस्कॉर्ट और उनके कोचों को बधाई दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पहली बार पैरालंपिक विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है।

कोरोना को लेकर मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग

देश में महामारी की स्थिति और वैक्सीनेशन पर हुई चर्चा

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है और यह समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि देश के 35 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक है, जबकि 30 जिलों में यह दर 5 से 10 प्रतिशत के बीच है। सरकार ने गुरुवार को कहा था कि देश की वयस्क आबादी में 58 प्रतिशत को



कोविड-19 टीकों की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है, वहीं 18 प्रतिशत को दोनों खुराकें दी गयी हैं। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि देश में अब तक 72 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के 34,973 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 3,31,74,954

हो गई है। जबकि इस दौरान 260 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,42,009 पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज अब घटकर 3.90 लाख हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में देश भर में संक्रमण से 37,681 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,23,42,299 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 3,90,646 है, जो कुल मामलों का 1.18 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.96 प्रतिशत है, जो

पिछले 11 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है। जबकि विकली पॉजिटिविटी रेट 2.31 प्रतिशत है, जो 77 दिनों से 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक 72,37,84,586 कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में रिकवरी रेट अब 97.49 प्रतिशत हो गया है। वहीं, इंडियन कार्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस के लिए 17,87,611 सैपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद देश में सैपल टेस्टिंग का आंकड़ा अब 53,86,04,854 हो गया है। वहीं बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 34,973 नए मामलों और 260 मौतों में केरल से सामने आए 26,200 नए मामले और 114 मौतें भी शामिल हैं।

अब गांवों को भी मिलेगी स्वच्छता की रैंकिंग, देश के 17,475 गांव का सर्वे कराएगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जलशाक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दो को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी)- 2021 लॉन्च किया। खुले में शौच से मुक्ति के बाद आडीएफ प्लस गांव बनाने की दिशा में आने वाले व्यवधानों को दूर करने और मिशन के कार्यक्रमों में तेजी लाना इस सर्वेक्षण का मुख्य लक्ष्य है। एसएसजी-2021 की रैंकिंग में आपके गांव में जलभराव की स्थिति, टोस और तरल कचरे सहित प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन सबसे अधिक फर्क डालेगा। समूह बैचकों, 17,475 गांवों के करीब 1.75 लाख परिवारों से और



मोबाइल एप पर मिलने वाला फीडबैक गांव की स्वच्छता की रैंकिंग तय करेगा। केंद्रीय जलशाक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2021

लॉन्च करने के साथ ही हिंदी-अंग्रेजी सहित तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में फीडबैक के लिए मोबाइल एप भी लॉन्च किया। सर्वेक्षण में फील्ड सर्वे 25 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक

चलेगा। पटेल ने कहा कि पिछले सर्वे से यह पता चला कि ग्रामीण भारत में स्वच्छ भारत पहुंच गया है। अब हमारी उपलब्धियां नए सर्वे में सामने आएंगी। स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छता सबसे बड़ा हथियार है। जो कुछ कमियां स्वतंत्र एजेंसी के सर्वे में सामने आएंगी, उससे सुधार का मौका मिलेगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के सचिव पंकज कुमार ने अनुसार, यह देश में अपने किस्म का सबसे बड़ा सर्वे है। राज्यों से अपील की कि वे बड़-चढ़कर सर्वे में हिस्सा लें और अपने गांव का नाम रोशन करने में मदद करें। अतिरिक्त सचिव अरुण बरोका ने कहा कि, एक विशेषज्ञ एजेंसी को बड़े सर्वे का जिम्मा

सौंपा गया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रिजल्ट का डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। 87 हजार से अधिक स्थानों का निरीक्षण- सर्वेक्षण में गांव, जिला और राज्यों को कुछ निर्धारित मानकों का प्रयोग करके रैंकिंग दी जाएगी। इस सर्वेक्षण के तहत देशभर के 698 जिलों के 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा। इन 17,450 गांवों, जिला और फिर राज्य की रैंकिंग के सर्वेक्षण के लिए 87,250 सार्वजनिक स्थानों (स्कूल, आंगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट/बाजार/धार्मिक स्थल) का दौरा किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी

हो सके, उसके लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन बनाई गई है। लोगों को एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर फीडबैक देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पिछली बार मोबाइल एप्लिकेशन पर तीन करोड़ फीडबैक आए थे। इस बार इसके चार करोड़ से ऊपर पहुंचने की संभावना है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इससे पहले वर्ष 2018 और 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कराया था। कोरोना महामारी के बीच वर्ष 2020 में यह सर्वेक्षण नहीं कराया गया। यह सर्वेक्षण केवल रैंकिंग देने की प्रक्रिया तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छता की आदत को एक जनादोलन बनाने का कार्यक्रम है।